[श्री सकलदीप राजभर]

डीकम्पोज़र का उत्पादन कराया जाए, साथ ही पूरे देश में इसका प्रचार-प्रसार कर किसानों को यह उपलब्ध कराया जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, सकलदीप जी। श्री शिव प्रताप शुक्ल जी।

Arbitrary increase in fee by private schools

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और सदन के माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सर, न केवल सदन के अंदर, बल्कि सदन के बाहर भी, दिल्ली ही नहीं, बल्कि दिल्ली के बाहर भी सभी लोग इस दंश से पीड़ित हैं। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वे प्राइमरी स्कूल्स हों, चाहे जो नए-नए विश्वविद्यालय बने हैं, वे हों, चाहे डिग्री कॉलेजेज़ हों, मेडिकल एजुकेशन हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ हों, नर्सिंग कॉलेजेज़ हो, इन सभी की यह स्थिति हो चुकी है कि आज वे अपनी फीस में कब और कितनी वृद्धि कर देंगे, इसका कोई अनुमान नहीं रह गया है। स्वाभाविक रूप से, परिवारों में बच्चे पैदा होंगे, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहेंगे, लेकिन अच्छी शिक्षा दिलाने की स्थिति में वे इस कारण नहीं आ पाते हैं, क्योंकि प्ले स्कूल्स और नर्सरी स्कूल्स में ही कहा जाता है कि 10 से 15 हजार रुपए दीजिए। बिल्डिंग फंड, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अलग से पैसा लिया जाता है और इसका परिणाम यह है कि नर्सरी स्कूल में बच्चों के प्रवेश के लिए लोग एक-एक लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश कैसे कराएं, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है? आज यही स्थिति स्कूलों की है, यही स्थिति कोचिंग्स की भी है। अगर कोई बच्चा यहाँ से पढ़कर निकलता है, तो वे उसका विज्ञापन पेपरों में देते हैं, लेकिन उस बच्चे का ही देते हैं, जो मेरिट में आ जाता है। उस विज्ञापन में दिखाते हैं कि यह मेरे स्कूल का बच्चा है, लेकिन अगर वही बच्चा पहले प्रवेश लेने के लिए जाता है, तो उसे कोई एक नए पैसे की भी छूट देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसकी परिणति यह हो गई है कि लोग असहाय हो गए हैं कि हम अपने बच्चे को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे एजुकेट कराएं? आज इसी नाते मैंने यह विषय आप सभी लोगों के संज्ञान में लाने का प्रयत्न किया है। मान्यवर, ऐसे ही मेडिकल एजुकेशन, और मैनेजमेंट के विषय हैं। अगर हम लोग आज इस सदन में बैठकर विचार नहीं करेंगे, अगर सदन के बाहर जाकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो ये जो कुकुरमुत्तों की तरह पैदा होने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोगों को कहीं न कहीं आकर्षित करते हैं और लोग अपने बच्चों को उनमें डाल देते हैं और बाद में यह पता लगता है कि वे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं - ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए, सरकार भी ध्यान दे। इसमें एकरूपता आनी चाहिए, जिससे फीस का कोई न कोई ढांचा बन सके।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री लाल सिंह वड़ोदिया (गुजरात): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री के.जे. एल्फोंस (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री के.जी. केन्ये (नागालैंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

प्रो. मनोज कुमार झा : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. सोनल मानसिंह (नाम निर्देशित): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करती हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Special Mentions. Shri B.K. Hariprasad.

SPECIAL MENTIONS

Demand to provide fund under the MGNREGS to Karnataka

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, MGNREGS is the biggest scheme and the only source of income for unskilled labours for their livelihood.